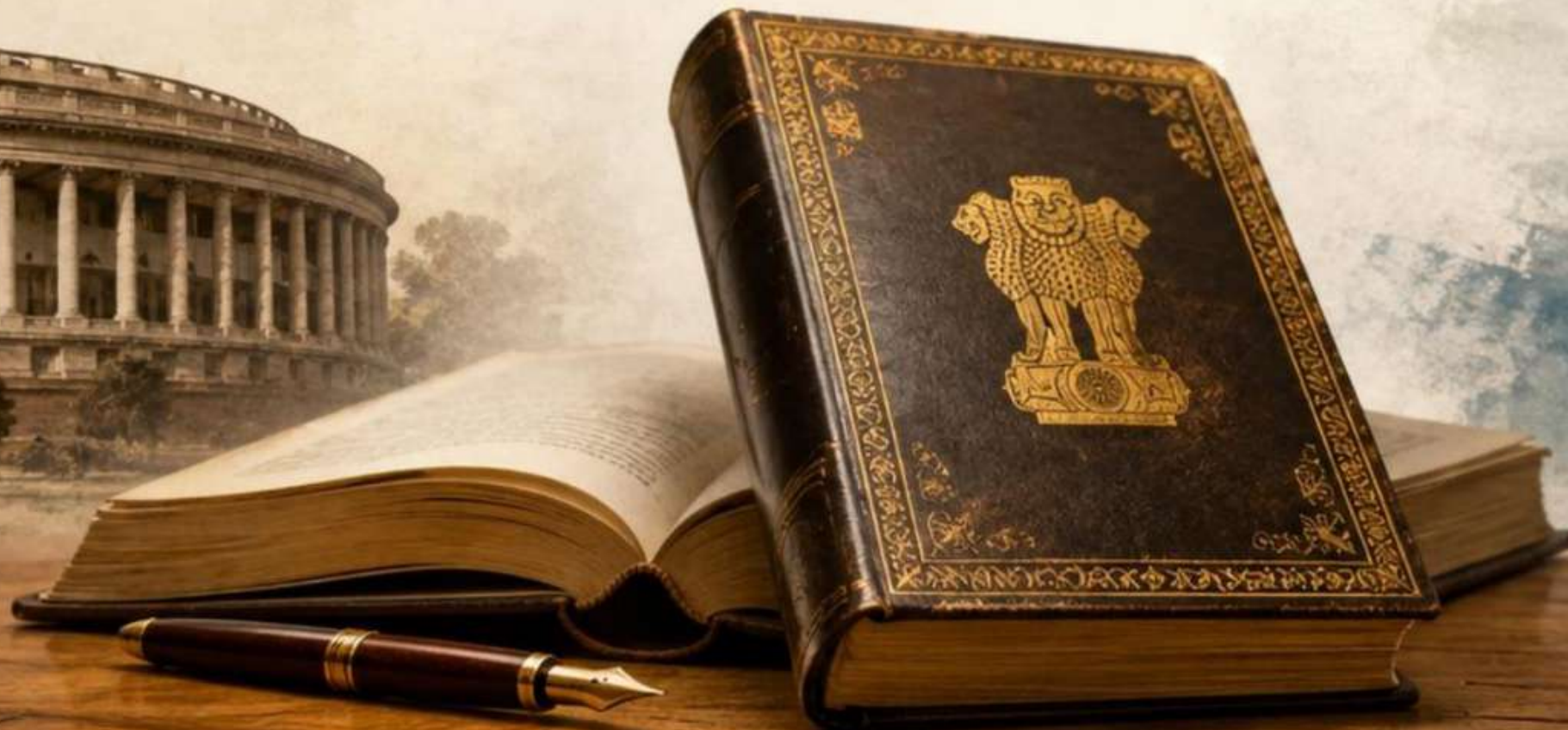


Historical Background of Constitution

संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि



HISTORICAL BACKGROUND OF INDIAN CONSTITUTION



Starting Point - प्रारंभिक बिंदु

- British constitutional development in India began with the Regulating Act, 1773.
- भारत में ब्रिटिश संवैधानिक विकास की शुरुआत 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट से हुई।
- British Parliament gradually introduced constitutional and administrative reforms.
- ब्रिटिश संसद ने धीरे-धीरे संवैधानिक और प्रशासनिक सुधार लागू किए।
- These reforms ultimately shaped the institutions of independent India.
- इन सुधारों ने अंततः स्वतंत्र भारत की संस्थाओं को आकार दिया।

Broad Phases - प्रमुख चरण

BEIC

- Company Rule → 1773-1858
- कंपनी शासन → 1773-1858
- Crown Rule → 1858-1947
- क्राउन शासन → 1858-1947
- Constitutional Development → 1773-1947
- संवैधानिक विकास → 1773-1947

COMPANY RULE (1773–1858)



Important Acts - महत्वपूर्ण अधिनियम

- Regulating Act, 1773 - रेग्युलेटिंग एक्ट, 1773 ✓
- Amending Act/Act of Settlement, 1781 ✓
- संशोधन अधिनियम/एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781 ✓
- Pitt's India Act, 1784 - पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 ✓✓
- Act of 1786 - 1786 का अधिनियम ✓
- Charter Act, 1793 - चार्टर एक्ट, 1793 ✓
- Charter Act, 1813 - चार्टर एक्ट, 1813 ✓
- Charter Act, 1833 - चार्टर एक्ट, 1833 ✓
- Charter Act, 1853 - चार्टर एक्ट, 1853 ✓

Major Turning Point - प्रमुख मोड़

- Regulating Act, 1773 was the first major attempt by the British Parliament to regulate the East India Company's affairs.
- 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने का पहला प्रमुख प्रयास था।

REGULATING ACT, 1773



Significance - महत्व

- First major constitutional step by British Government to:
- ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला प्रमुख संवैधानिक कदम था: ✓
- Control East India Company
- ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना
- Regulate its administration ✓
- इसके प्रशासन को विनियमित करना
- Establish a centralised administrative structure
- एक केंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना स्थापित करना

Governor-General of Bengal

बंगाल का गवर्नर-जनरल ✓

Office of Governor-General of Bengal created.

- बंगाल के गवर्नर-जनरल का पद सृजित किया गया।
- Assisted by an Executive Council of 4 members.
- उन्हें 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी।
- ✓ Warren Hastings became the first Governor-General of Bengal.
- वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर-जनरल बने।

Presidencies - प्रेसीडेंसी

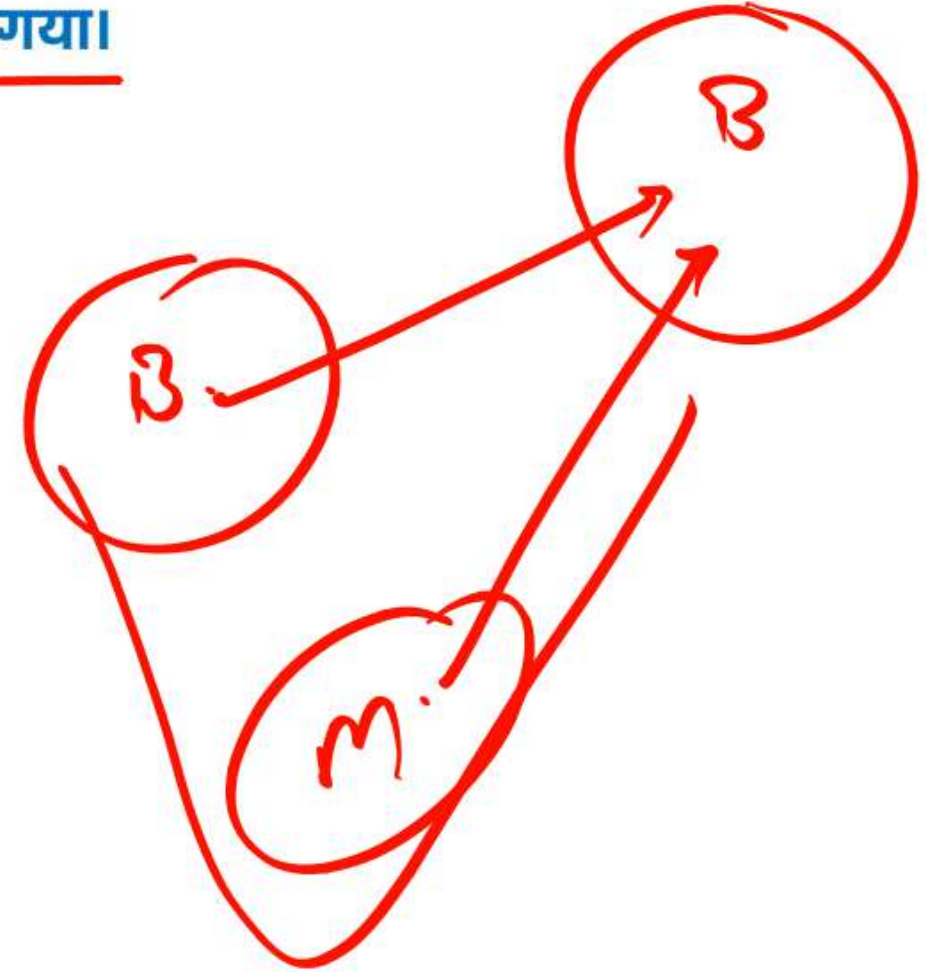
- Bombay and Madras were subordinated to the Governor-General of Bengal in specified matters.
- निर्दिष्ट मामलों में बॉम्बे और मद्रास को बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिया गया।

Judiciary - न्यायपालिका

- Provided for establishment of Supreme Court at Calcutta in 1774.
- 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया।
- Composition - संरचना:
- Chief Justice - मुख्य न्यायाधीश ✓
- Three other judges - तीन अन्य न्यायाधीश

Other Provisions - अन्य प्रावधान

- Company servants prohibited from:
- कंपनी के कर्मचारियों को निम्नलिखित कार्यों से प्रतिबंधित किया गया:
- Private trade - निजी व्यापार ✓
- Accepting bribes/gifts from natives - भारतीयों से रिश्वत/उपहार स्वीकार करना
- Court of Directors required to report:
- कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को निम्नलिखित की रिपोर्ट देना आवश्यक किया गया:
- Revenue - राजस्व ✓
- Civil affairs - नागरिक मामले ✓
- Military affairs - सैन्य मामले ✓



AMENDING ACT / ACT OF SETTLEMENT, 1781



Why Introduced?

क्यों लाया गया?

- To correct defects of the Regulating Act, 1773.
- 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए।
- Also known as Act of Settlement, 1781.
- इसे 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है।

Major Provisions - प्रमुख प्रावधान

- Governor-General and Council exempted from Supreme Court jurisdiction for:
- गवर्नर-जनरल और उनकी परिषद को निम्नलिखित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया:
 - Official acts - आधिकारिक कार्य
- Company servants exempted from Supreme Court jurisdiction for:
- कंपनी के कर्मचारियों को निम्नलिखित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया:
 - Official acts - आधिकारिक कार्य

Revenue Matters - राजस्व संबंधी मामले

- Revenue collection matters excluded from Supreme Court jurisdiction.
- राजस्व संग्रह से संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया।

Jurisdiction of Supreme Court - सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र

- Supreme Court given jurisdiction over inhabitants of Calcutta.
- सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता के निवासियों पर अधिकार क्षेत्र प्रदान किया गया।
- Personal laws recognised:
- व्यक्तिगत कानूनों को मान्यता दी गई:
- Hindus → Hindu law
- हिंदू → हिंदू कानून
- Muslims → Muslim law
- मुस्लिम → मुस्लिम कानून

Appeals - अपील

- Appeals from Provincial Courts could be taken to:
- प्रांतीय न्यायालयों के विरुद्ध अपील की जा सकती थी:
- Governor-General-in-Council
- गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल के समक्ष
- Instead of Supreme Court.
- सर्वोच्च न्यायालय के बजाय।

PITT'S INDIA ACT, 1784



V. Imp.

Background - पृष्ठभूमि

- Introduced by British Prime Minister William Pitt.
- ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- Distinguished between:
- इसके द्वारा अंतर किया गया:
 - Commercial functions (वाणिज्यिक कार्य)
 - Political functions (राजनीतिक कार्य)

Dual System of Control - नियंत्रण की द्वैध व्यवस्था

- Court of Directors - कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स
- Commercial affairs - वाणिज्यिक मामले
- Board of Control - बोर्ड ऑफ कंट्रोल
- Political affairs - राजनीतिक मामले

Board of Control - बोर्ड ऑफ कंट्रोल

- Supervised and directed:
- निगरानी और निर्देशन करता था:
- Civil administration
- नागरिक प्रशासन
- Military administration
- सैन्य प्रशासन
- British possessions in India
- भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों

Significance - महत्व

- Established Dual Government/System of Control.
- द्वैध शासन/नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की।
- Increased British Government's control over Company affairs.
- कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया।

Important Terminology - महत्वपूर्ण शब्दावली

- Court of Directors + Board of Control = Dual Control
- कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स + बोर्ड ऑफ कंट्रोल = द्वैध नियंत्रण

ACT OF 1786



Background - पृष्ठभूमि

- Lord Cornwallis was appointed Governor-General.
- लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया।
- He demanded additional powers.
- उन्होंने अतिरिक्त शक्तियों की मांग की।

Major Provisions - प्रमुख प्रावधान

- Governor-General empowered to:
- गवर्नर-जनरल को यह शक्ति दी गई कि वे:
- Override the decision of his Council in special cases.
- विशेष मामलों में अपनी परिषद के निर्णय को अस्वीकार कर सकें।
- Governor-General could also serve as:
- गवर्नर-जनरल निम्न पद भी धारण कर सकता था:
- Commander-in-Chief
- कमांडर-इन-चीफ (सेनापति)

Significance - महत्व

- Strengthened the authority of Governor-General.
- गवर्नर-जनरल के अधिकार को मजबूत किया।
- Further centralised executive power.
- कार्यकारी शक्ति को और अधिक केंद्रीकृत किया।

CHARTER ACT, 1793

V. Imp.



Major Provisions - प्रमुख प्रावधान

- Extended overriding powers of Governor-General over his Council.
- गवर्नर-जनरल की अपनी परिषद पर अधिभावी शक्तियों का विस्तार किया गया।
- These powers extended to future:
- ये शक्तियाँ भविष्य में निम्न पर भी लागू थीं:
- Governor-Generals
- गवर्नर-जनरल
- Governors
- गवर्नर

Trade - व्यापार

- Extended Company's trade monopoly for another 20 years.
- कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।

Commander-in-Chief - कमांडर-इन-चीफ

- Could be a member of Governor-General's Council only if specifically appointed.
- कमांडर-इन-चीफ को केवल विशेष रूप से नियुक्त किए जाने पर ही गवर्नर-जनरल की परिषद का सदस्य बनाया जा सकता था।

Financial Provision - वित्तीय प्रावधान

- Salaries of: - वेतन: ✓
- Board of Control - बोर्ड ऑफ कंट्रोल ✓
- Its staff - इसके कर्मचारियों का ✓
- To be paid from Indian revenues.
- भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाना था।

CHARTER ACT, 1813



Major Significance - प्रमुख महत्व

- Ended Company's trade monopoly in India. ✓
- भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।

Exception - अपवाद

- Company retained monopoly over:
- कंपनी का एकाधिकार निम्नलिखित पर बना रहा: ✓
- Tea trade - चाय का व्यापार ✓
- Trade with China - चीन के साथ व्यापार ✓

British Merchants - ब्रिटिश व्यापारी

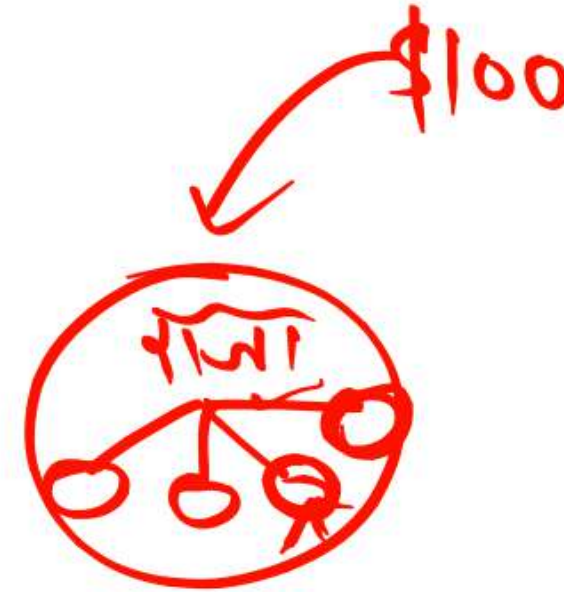
- Indian trade opened to other British merchants.
- भारतीय व्यापार को अन्य ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया।

Religion & Education - धर्म और शिक्षा

- Christian missionaries allowed to come to India.
- ईसाई मिशनरियों को भारत आने की अनुमति दी गई।
- Promoted spread of Western education.
- पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया गया।

Local Government - स्थानीय सरकार

- Local governments authorised to:
- स्थानीय सरकारों को यह अधिकार दिया गया कि वे:
- Impose taxes - कर लगा सकें
- Penalise non-payment of taxes - करों का भुगतान न करने पर दंड दे सकें



SSC Exam Point - SSC परीक्षा बिंदु

- 1813 → Company monopoly ended except Tea + China trade
- 1813 → कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ, केवल चाय + चीन के व्यापार को छोड़कर।

CHARTER ACT, 1833

Importance - महत्व

- Considered a major step towards centralisation.
- इसे केंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया।

Governor-General of India - भारत का गवर्नर-जनरल

- Governor-General of Bengal became:
- बंगाल का गवर्नर-जनरल बन गया:
- Governor-General of India
- भारत का गवर्नर-जनरल
- First Governor-General of India:
- भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल:
- Lord William Bentinck
- लॉर्ड विलियम बेंटिंक

Legislative Powers - विधायी शक्तियाँ

- Governor-General of India received:
- भारत के गवर्नर-जनरल को प्राप्त हुई:
- Complete civil and military authority over British India.
- ब्रिटिश भारत पर पूर्ण नागरिक और सैन्य अधिकार।
- Governor-General received exclusive legislative powers for British India.
- गवर्नर-जनरल को ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियाँ प्रदान की गईं।

Presidencies - प्रेसीडेंसी

- **Bombay and Madras lost their legislative powers.**
- बॉम्बे और मद्रास ने अपनी विधायी शक्तियाँ खो दीं।

1857

Company - कंपनी

- **Company's commercial activities ended.**
- कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियाँ समाप्त कर दी गईं।
- **Company became a purely administrative body.**
- कंपनी केवल एक प्रशासनिक संस्था बन गई।

Territories - क्षेत्र

- **Company territories held in trust for the British Crown.**
- कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश क्राउन के लिए न्यास के रूप में रखा गया।

SSC Fact - SSC तथ्य

- **1833 → First Governor-General of India = William Bentinck**
- 1833 → भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल = विलियम बेंटिंक

CHARTER ACT, 1833 — OTHER FEATURES



Civil Services – सिविल सेवाएँ

- Introduced principle of open competition for recruitment.
- भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया।
- Indians theoretically not excluded from civil services.
- सैद्धांतिक रूप से भारतीयों को सिविल सेवाओं से बाहर नहीं रखा गया।

Legislative Council – विधायी परिषद

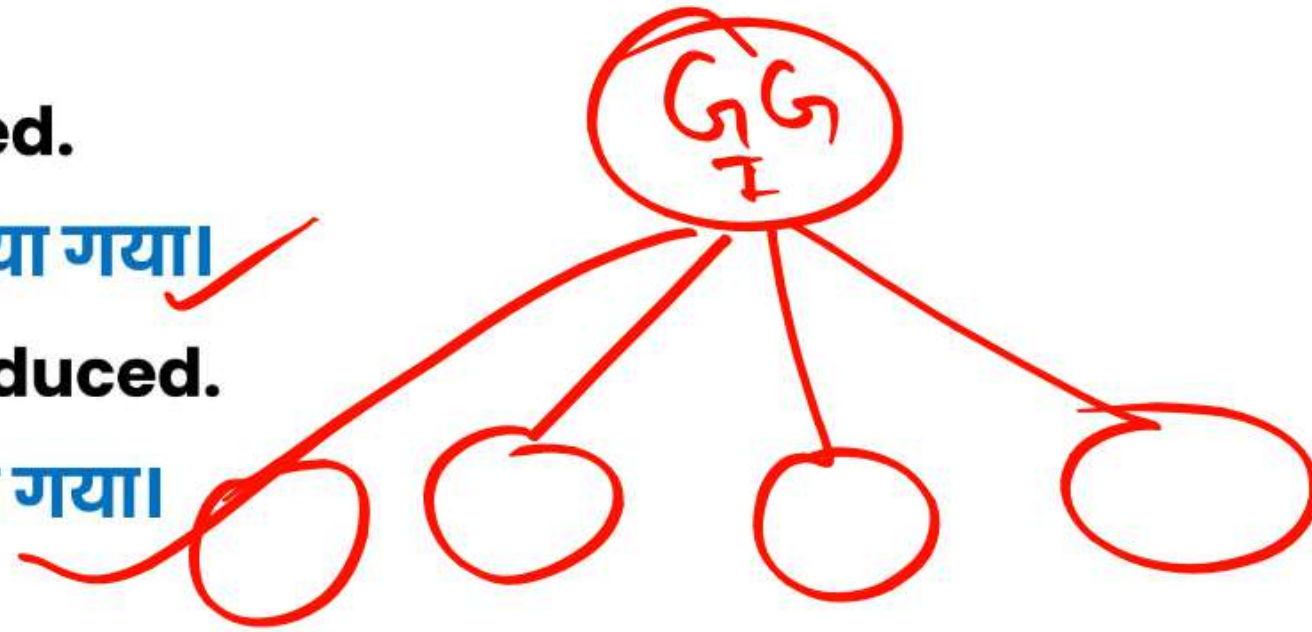
- Introduced additional legislative member.
- एक अतिरिक्त विधायी सदस्य का प्रावधान किया गया।
- Beginning of specialised legislative machinery.
- विशेषीकृत विधायी तंत्र की शुरुआत हुई।

Law Commission – विधि आयोग

- Led to development of systematic codification of laws.
- कानूनों के व्यवस्थित संहिताकरण के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ।

Centralisation - केंद्रीकरण

- Strong central authority established.
- एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण स्थापित किया गया। ✓
- Provincial legislative autonomy reduced.
- प्रांतीय विधायी स्वायत्तता को कम कर दिया गया। ✓



Significance - महत्व

- Major step towards: ✓
- निम्नलिखित की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम:
- Centralised administration ✓
- केंद्रीकृत प्रशासन
- Legislative uniformity ✓
- विधायी एकरूपता
- Modern civil service system
- आधुनिक सिविल सेवा प्रणाली

CHARTER ACT, 1853

Imp.



Significance - महत्व

- Last of the Charter Acts.
- चार्टर एक्ट्स में अंतिम अधिनियम।
- Important constitutional landmark.
- एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मील का पत्थर।

Legislative-Executive Separation - विधायी-कार्यकारी पृथक्करण

- Separated:
- पृथक किए गए:
- Legislative functions - विधायी कार्य ✓
- Executive functions - कार्यकारी कार्य ✓
- Governor-General's Council received additional legislative members. ✓
- गवर्नर-जनरल की परिषद में अतिरिक्त विधायी सदस्यों को शामिल किया गया।

Legislative Council - विधायी परिषद

- Created separate Indian (Central) Legislative Council.
- एक अलग भारतीय (केंद्रीय) विधायी परिषद का गठन किया गया।
- Functioned like a mini-Parliament.
- यह एक छोटी संसद (मिनी-पार्लियामेंट) की तरह कार्य करती थी।

Civil Services - सिविल सेवाएँ ✓

- Introduced open competition for civil service recruitment.
- सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई।
- Macaulay Committee, 1854 associated with this development.
- मैकॉले समिति, 1854 इस विकास से संबंधित थी। ✓

Representation - प्रतिनिधित्व ✓

- Introduced local representation in Central Legislative Council.
- केंद्रीय विधायी परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई।
- Some members nominated through provincial governments.
- कुछ सदस्यों को प्रांतीय सरकारों के माध्यम से नामित किया गया।

COMPANY RULE — COMPLETE REVISION



Act	Most Important Feature
1773	Governor-General of Bengal + Supreme Court
1781	Corrected Regulating Act
1784	Board of Control + Dual Control
1786	Governor-General's overriding power
1793	Company monopoly extended ✓
1813	Trade monopoly ended except Tea & China ✓ ✓
1833	Governor-General of India + Company trade ended
1853	Legislative-executive separation + open competition

CROWN RULE (1858–1947)

Viceroy

Beginning - शुरुआत

- Revolt of 1857 became the immediate turning point.
- 1857 का विद्रोह तत्काल निर्णायक मोड़ बना।
- British Crown assumed direct responsibility for Indian administration.
- ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय प्रशासन की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी संभाल ली।

Major Constitutional Developments - प्रमुख संवैधानिक विकास

- Government of India Act, 1858 ✓
- भारत सरकार अधिनियम, 1858 ✓
- Indian Councils Act, 1861 ✓
- भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 ✓
- Indian Councils Act, 1892 ✓
- भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 ✓
- Indian Councils Act, 1909 ✓
- भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 ✓
- Government of India Act, 1919 ✓
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 ✓
- Government of India Act, 1935 ✓
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 ✓
- Indian Independence Act, 1947 ✓
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ✓

V. J. P.

GOVERNMENT OF INDIA ACT, 1858



Background - पृष्ठभूमि

- Passed after the Revolt of 1857.
- 1857 के विद्रोह के बाद इसे पारित किया गया।
- Ended East India Company's rule.
- ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया।

Major Change - प्रमुख परिवर्तन

- Power transferred from:
- शक्ति का हस्तांतरण हुआ:
- East India Company → British Crown
- ईस्ट इंडिया कंपनी → ब्रिटिश क्राउन

New Designation - नया पदनाम

- India to be governed in the name of:
- भारत का शासन निम्नलिखित के नाम पर चलाया जाना था:
- British Crown
- ब्रिटिश क्राउन

Governor-General - गवर्नर-जनरल

- Also became:
- यह पद भी बन गया:
- Viceroy of India
- भारत का वायसराय ✓
- First Viceroy:
- प्रथम वायसराय: ✓
- Lord Canning
- लॉर्ड कैनिंग

Administrative Changes → प्रशासनिक परिवर्तन

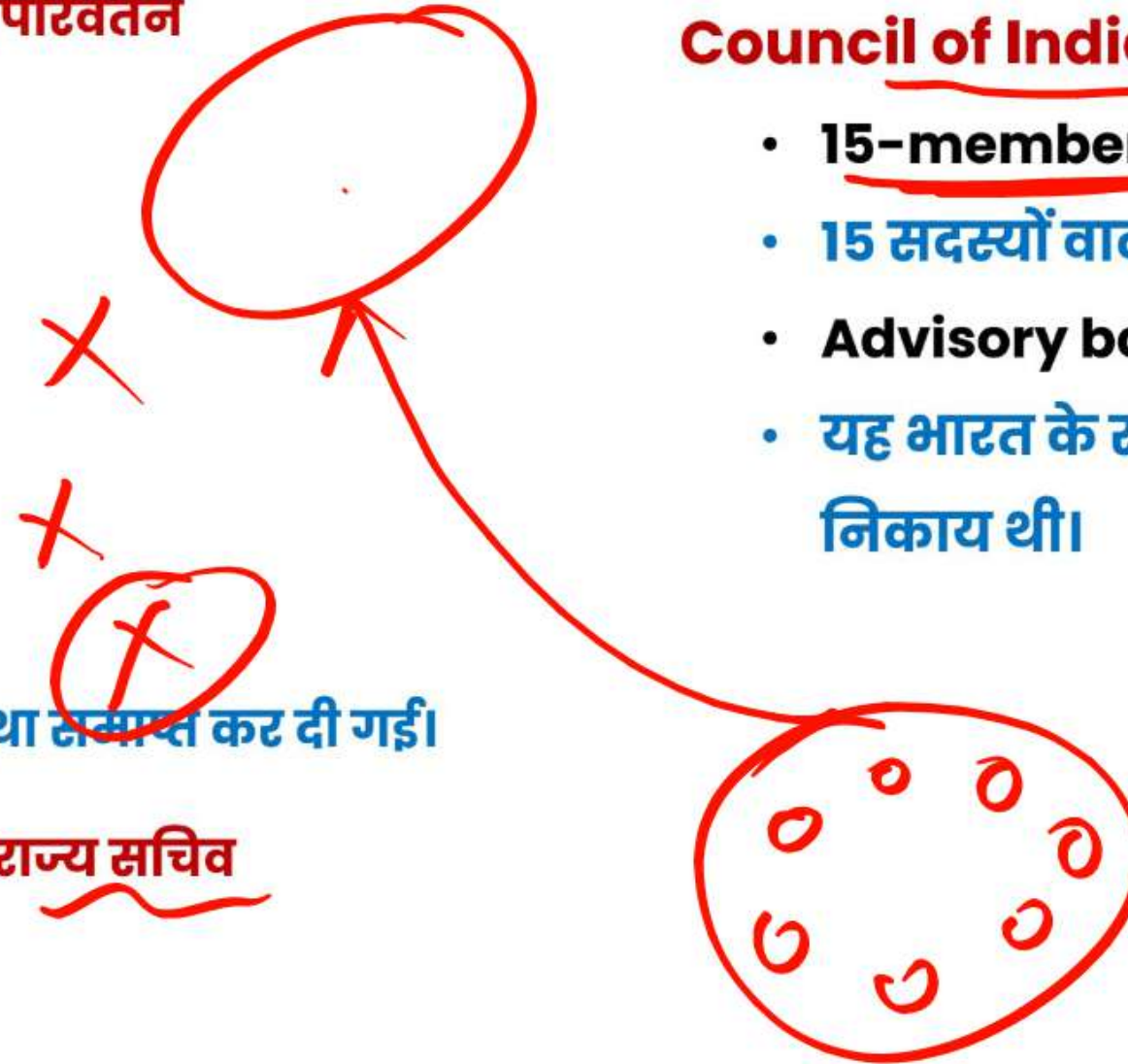
- Abolished:
- समाप्त किए गए:
- Court of Directors
- कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स (निदेशक मंडल)
- Board of Control
- बोर्ड ऑफ कंट्रोल (नियंत्रण मंडल)
- Ended system of Dual Control.
- द्वैध नियंत्रण (Dual Control) की व्यवस्था समाप्त कर दी गई।

Secretary of State for India → भारत के राज्य सचिव

- New office created.
- नया पद सृजित किया गया।
- Complete authority over Indian administration.
- भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार।
- Member of British Cabinet.
- ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य।
- Responsible to British Parliament.
- ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी।

Council of India → भारत परिषद

- 15-member Council established.
- 15 सदस्यों वाली परिषद की स्थापना की गई।
- Advisory body to Secretary of State.
- यह भारत के राज्य सचिव के लिए एक सलाहकार निकाय थी।





BACKGROUND / पृष्ठभूमि

- British Government realised the need for Indian cooperation after 1857.
- 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सहयोग की आवश्यकता को महसूस किया।



LEGISLATIVE REPRESENTATION / विधाची प्रतिनिधित्व

- Indians associated with legislative process.
- भारतीयों को विधाची प्रक्रिया से जोड़ा गया।
- Governor-General could nominate non-official Indian members.
- गवर्नर-जनरल गैर-सरकारी भारतीय सदस्यों को नामित कर सकता था।



IMPORTANT EXAMPLE / महत्वपूर्ण उदाहरण

Lord Canning nominated:

- Raja of Benaras बनारस के राजा
- Maharaja of Patiala पटियाला के महाराजा
- Sir Dinkar Rao सर दिनकर राव



Raja of Benaras
बनारस के राजा



Maharaja of Patiala
पटियाला के महाराजा



Sir Dinkar Rao
सर दिनकर राव

INDIAN COUNCILS ACT, 1861

इंडियन काउंसिल्स एक्ट, 1861

A STEP TOWARDS INDIAN PARTICIPATION IN GOVERNANCE

शासन में भारतीय भागीदारी की दिशा में एक कदम

INDIAN COUNCILS ACT, 1861
इंडियन काउंसिल्स एक्ट, 1861



British Realisation
ब्रिटिश सरकार की समझ



Indian Association in
Legislative Process

विधाची प्रक्रिया में भारतीयों की भागीदारी



Nomination of
Indian Members

भारतीय सदस्यों का नामांकन



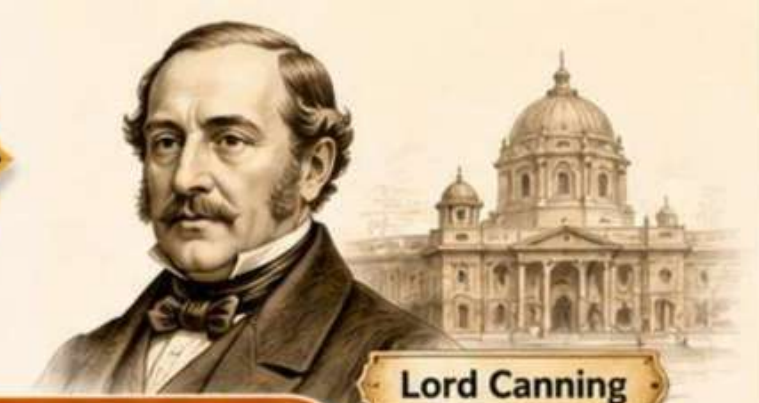
Towards Indian Participation
in Governance

शासन में भारतीय भागीदारी की ओर



DECENTRALISATION REFORMS

विकेन्द्रीकरण सुधार



Lord Canning



1 DECENTRALISATION विकेन्द्रीकरण

- Legislative powers restored to:
विधाची शक्तियाँ पुनः प्रदान की गई:
- Bombay (बॉम्बे) ✓
- Madras (मद्रास) ✓



2 SIGNIFICANCE महत्व

- Reversed excessive centralisation.
अत्यधिक केन्द्रीकरण को समाप्त किया गया। ✓
- Beginning of legislative decentralisation.
विधाची विकेन्द्रीकरण की शुरुआत।



3 NEW LEGISLATIVE COUNCILS नई विधाची परिषदें

- Bengal (बंगाल) ✓
- North-Western Provinces
(उत्तर-पश्चिम प्रान्त) ✓
- Punjab (पंजाब) ✓



4 PORTFOLIO SYSTEM पोर्टफोलियो प्रणाली

- Recognised Portfolio System.
पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई।
- Introduced by Lord Canning.
लॉर्ड कैनिंग द्वारा प्रारंभ की गई।



5 ORDINANCE POWER अध्यादेश शक्ति

- Viceroy could issue ordinances during emergencies.
आपातकाल के दौरान वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता था ✓
- Ordinance validity:
अध्यादेश की वैधता:
• 6 months (6 माह) ✓



SUMMARY / सारांश

These reforms marked an important step towards balanced governance by distributing legislative powers and recognising provincial autonomy. इन सुधारों ने विधाची शक्तियों के वितरण और प्रांतीय स्वायत्तता की मान्यता देकर संतुलित शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया।



INDIAN COUNCILS ACT, 1892 ✓



Legislative Councils → विधान परिषदें ✓

- Increased number of additional members.
- अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ✓
- Both Central and Provincial Councils expanded.
- केंद्रीय और प्रांतीय दोनों परिषदों का विस्तार किया गया। ✓

Legislative Functions → विधायी कार्य

- Members allowed to:
- सदस्यों को अनुमति दी गई कि वे:
- Ask questions
- प्रश्न पूछ सकें। ✓
- Discuss budget
- बजट पर चर्चा कर सकें। ✓
- Address questions to executive
- कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकें। ✓

Representation → प्रतिनिधित्व ✓

- Beginning of indirect election principle. ✓
- अप्रत्यक्ष निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत हुई। ✓
- Members nominated on recommendations of:
- सदस्यों का नामांकन निम्नलिखित की सिफारिशों पर किया गया: ✓
- Provincial Councils - प्रांतीय परिषदें ✓
- Bengal Chamber of Commerce - बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स ✓
- Local bodies - स्थानीय निकाय ✓
- Municipalities - नगरपालिकाएँ ✓
- Universities - विश्वविद्यालय ✓
- Trade associations - व्यापारिक संघ ✓
- Zamindars - जमींदार ✓

Important Limitation → महत्वपूर्ण सीमा

- Word "election" was not officially used. ✓
- "निर्वाचन (Election)" शब्द का आधिकारिक रूप से प्रयोग नहीं किया गया। ✓
- System described as nomination on recommendation. ✓
- इस व्यवस्था को सिफारिश के आधार पर नामांकन के रूप में वर्णित किया गया। ✓

INDIAN COUNCILS ACT, 1909 (MORLEY-MINTO REFORMS)



Important Personalities → महत्वपूर्ण व्यक्तित्व

- John Morley - जॉन मॉर्ले
 - Secretary of State for India
 - भारत के राज्य सचिव
- Lord Minto - लॉर्ड मिंटो
 - Viceroy of India
 - भारत के वायसराय

1906

Legislative Councils → विधान परिषदें

- Size considerably increased.
- आकार में काफी वृद्धि की गई।
- Central Legislative Council:
- केंद्रीय विधान परिषद:
 - Members increased from 16 to 60
 - सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई।
- Provincial councils also expanded.
- प्रांतीय परिषदों का भी विस्तार किया गया।

Majority → बहुमत

- Official majority retained at Centre.
- केंद्र में सरकारी बहुमत बरकरार रखा गया। ✓
- Provincial councils allowed non-official majority.
- प्रांतीय परिषदों में गैर-सरकारी बहुमत की अनुमति दी गई।

Legislative Functions → विधायी कार्य

- Greater deliberative powers.
- अधिक विचार-विमर्श संबंधी शक्तियाँ प्रदान की गईं। ✓
- Questions and resolutions permitted.
- प्रश्न पूछने और प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई।

Executive Association → कार्यपालिका में भारतीयों की भागीदारी

- Indians associated with executive councils.
- भारतीयों को कार्यकारी परिषदों में शामिल किया गया।
- Satyendra Prasad Sinha became first Indian member of Viceroy's Executive Council.
- सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने।

Imp

MORLEY-MINTO REFORMS — SEPARATE ELECTORATE



Most Important Feature → सबसे महत्वपूर्ण विशेषता

- Introduced separate electorate for Muslims.
- मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था शुरू की गई।

Meaning → अर्थ

- Muslim members elected only by:
- मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल इनके द्वारा किया जाता था:
- Muslim voters
- मुस्लिम मतदाता

Significance → महत्व

- Institutionalised communal representation.
- साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को संस्थागत रूप दिया गया।
- Created separate political representation based on religion.
- धर्म के आधार पर अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई।

Other Provisions → अन्य प्रावधान

- Separate representation for:
- अलग प्रतिनिधित्व दिया गया:
- Presidency corporations - प्रेसीडेंसी निगमों को
- Chambers of Commerce - चैंबर ऑफ कॉमर्स को
- Universities - विश्वविद्यालयों को
- Zamindars - जमींदारों को

Famous Association → प्रसिद्ध संबोधन

- Lord Minto → Father of Communal Electorate
- लॉर्ड मिंटो → साम्प्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था के जनक

SSC Exam Alert → SSC परीक्षा अलर्ट

- 1909 → Separate Electorate for Muslims
- 1909 → मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था
- Do NOT confuse with:
- इसे इसके साथ भ्रमित न करें:
- Communal Award → 1932
- साम्प्रदायिक निर्णय (Communal Award) → 1932

GOVERNMENT OF INDIA ACT, 1919

MONTAGU-CHELMSFORD REFORMS



Background - पृष्ठभूमि

- British Government declared in 1917:
- ब्रिटिश सरकार ने 1917 में घोषणा की:
- Gradual introduction of responsible government in India.
- भारत में उत्तरदायी शासन की क्रमिक स्थापना की जाएगी।

Act → अधिनियम

- Government of India Act, 1919
- भारत सरकार अधिनियम, 1919
- Came into force in 1921.
- यह 1921 में लागू हुआ।

Major Features → प्रमुख विशेषताएँ

- Division of subjects into:
- विषयों का विभाजन किया गया:
- Central subjects
- केंद्रीय विषय
- Provincial subjects
- प्रांतीय विषय
- Based on Devolution Rules.
- यह व्यवस्था (हस्तांतरण नियमों) पर आधारित थी।

Objective → उद्देश्य

- Transfer some administrative authority from Centre to Provinces.
- कुछ प्रशासनिक शक्तियों को केंद्र से प्रांतों को हस्तांतरित करना।

Provincial Government → प्रांतीय सरकार

- Introduced Dyarchy.
- द्वैध शासन (Dyarchy) की शुरुआत की गई।

SSC Fact → SSC तथ्य

- 1919 → Dyarchy in Provinces
- 1919 → प्रांतों में द्वैध शासन

DYARCHY UNDER THE ACT OF 1919



Meaning → अर्थ

- Dyarchy = Dual Government
- द्वैध शासन (Dyarchy) = दोहरी सरकार
- Provincial Subjects Divided Into:
- प्रांतीय विषयों को विभाजित किया गया:

1. Reserved Subjects - आरक्षित विषय

- Police - पुलिस ✓
- Administration of Justice - न्याय प्रशासन ✓
- Land Revenue - भू-राजस्व ✓
- Finance - वित्त ✓
- Prisons - जेल / कारागार ✓

Administered by → द्वारा प्रशासित

- Governor
- गवर्नर / राज्यपाल
- Executive Councillors
- कार्यकारी पार्षद
- Not responsible to Provincial Legislature
- प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे।

2. Transferred Subjects → हस्तांतरित विषय

- Education ✓
- शिक्षा ✓
- Public Health
- सार्वजनिक स्वास्थ्य ✓
- Agriculture
- कृषि ✓
- Local Self-Government
- स्थानीय स्वशासन ✓

Administered by → द्वारा प्रशासित

- Ministers
- मंत्रियों द्वारा)
- Responsible to Provincial Legislature
- प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे।

Why Called Dyarchy?

इसे द्वैध शासन क्यों कहा गया?

- Two authorities administered provincial subjects.
- प्रांतीय विषयों का प्रशासन दो प्राधिकरणों द्वारा किया जाता था। ✓

Result → परिणाम

- Experiment largely unsuccessful.
- यह प्रयोग काफी हद तक असफल रहा।

OTHER FEATURES OF GOVERNMENT OF INDIA ACT, 1919



Bicameralism → द्विसदनीय व्यवस्था

- Introduced bicameral legislature at Centre.
- केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की गई।
- Two Houses:
- दो सदन:
- Council of State
- राज्य परिषद
- Legislative Assembly
- विधान सभा

Elections → निर्वाचन

- Direct elections introduced.
- प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई।

Communal Representation

साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व

- Extended separate electorates to:
- पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इन समुदायों तक विस्तारित की गई:
- Sikhs - सिख
- Indian Christians - भारतीय ईसाई
- Anglo-Indians - एंग्लो-इंडियन
- Europeans - यूरोपीय

Franchise → मताधिकार ✓

- Limited number of people received voting rights.
- सीमित संख्या में लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया।
- Based on:
- आधार था:
- Property - संपत्ति ✓
- Tax - कर ✓
- Other qualifications - अन्य योग्यताएँ ✓

Public Service → लोक सेवा ✓

- Provided for establishment of:
- स्थापना का प्रावधान किया गया:
- Public Service Commission
- लोक सेवा आयोग
- Central Public Service Commission established in 1926.
- केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई।

Other → अन्य

- Provincial and Central budgets separated.
- प्रांतीय और केंद्रीय बजट को अलग कर दिया गया।
- Chamber of Princes established in 1921.
- चैंबर ऑफ प्रिंसेस (नरेश मंडल) की स्थापना 1921 में हुई।

SIMON COMMISSION, 1927



Appointment → नियुक्ति

- British Government appointed a 7-member statutory commission.
- ब्रिटिश सरकार ने 7 सदस्यों वाले एक वैधानिक आयोग की नियुक्ति की।
- Chairman:
- अध्यक्ष:
- Sir John Simon
- सर जॉन साइमन

Purpose → उद्देश्य

- Review working of constitutional reforms.
- संवैधानिक सुधारों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।
- Recommend changes for future constitutional development.
- भविष्य के संवैधानिक विकास के लिए बदलावों की सिफारिश करना।

Composition → संरचना

- All members were British.
- सभी सदस्य ब्रिटिश थे।
- No Indian member
- कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था।

Indian Response → भारतीय प्रतिक्रिया

- Widely boycotted.
- व्यापक रूप से बहिष्कार किया गया।
- Famous slogan:
- प्रसिद्ध नारा:
- "Simon Go Back"
- "साइमन वापस जाओ"

Report → रिपोर्ट

- Submitted in 1930.
- रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत की गई।

Recommendations → सिफारिशें

- Abolition of dyarchy in provinces.
- प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति।
- Extension of responsible government.
- उत्तरदायी शासन का विस्तार।
- Establishment of federation.
- संघीय व्यवस्था की स्थापना।
- Continuation of communal electorates.
- साम्प्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखना।

ROUND TABLE CONFERENCES & WHITE PAPER



Round Table Conferences → गोलमेज सम्मेलन

- Held in London.
- लंदन में आयोजित किए गए।
- Discussed constitutional future of India.
- भारत के संवैधानिक भविष्य पर चर्चा की गई।
- Participants included:
 - प्रतिभागियों में शामिल थे:
 - British Government - ब्रिटिश सरकार
 - British India - ब्रिटिश भारत
 - Indian princely states - भारतीय रियासतें

White Paper → श्वेत पत्र

- Prepared on constitutional reforms.
- संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया।
- Submitted for consideration of:
 - विचार के लिए प्रस्तुत किया गया:
- Joint Select Committee of British Parliament
- ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति

Outcome → परिणाम

- Recommendations of Joint Select Committee incorporated, with modifications, into:
 - संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों को संशोधनों के साथ इसमें शामिल किया गया:
- Government of India Act, 1935
- भारत सरकार अधिनियम, 1935

COMMUNAL AWARD, 1932



Announced By → द्वारा घोषित

- **British Prime Minister:**
- **ब्रिटिश प्रधानमंत्री:**
- **Ramsay MacDonald**
- **रैम्से मैकडोनाल्ड**

Purpose → उद्देश्य

- **Separate representation for various communities.**
- **विभिन्न समुदायों के लिए अलग-अलग प्रतिनिधित्व प्रदान करना।**

Communities → समुदाय

- **Muslims - मुसलमान**
- **Sikhs - सिख**
- **Indian Christians - भारतीय ईसाई**
- **Anglo-Indians - एंग्लो-इंडियन**
- **Europeans - यूरोपीय**
- **Depressed Classes - दलित वर्ग / वंचित वर्ग**

Gandhi's Opposition → गांधी का विरोध

- **Gandhi opposed separate electorate for Depressed Classes.**
- **गांधी ने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था का विरोध किया।**
- **Began fast in:**
- **उपवास शुरू किया:**
- **Yerawada Jail, Poona**
- **यरवदा जेल, पूना**

Poona Pact → पूना समझौता

- Agreement between:
- समझौता हुआ:
- Mahatma Gandhi
- महात्मा गांधी
- Dr. B.R. Ambedkar
- डॉ. बी. आर. अंबेडकर

Result → परिणाम

- Joint electorate retained.
- संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था बरकरार रखी गई।
- Reserved seats provided for Depressed Classes.
- दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया।

GOVERNMENT OF INDIA ACT, 1935



Significance → महत्व

- Major constitutional milestone.
- एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मील का पत्थर।
- Lengthy and detailed Act.
- एक विस्तृत और व्यापक अधिनियम।
- 321 Sections + 10 Schedules
- 321 धाराएँ + 10 अनुसूचियाँ

Federal Scheme → संघीय योजना

- Proposed All-India Federation.
- अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया।
- Units:
- इकाइयाँ:
- British Indian Provinces - ब्रिटिश भारतीय प्रांत
- Princely States - देशी रियासतें

Distribution of Powers → शक्तियों का विभाजन

- Three Lists:
- तीन सूचियाँ:
- Federal List - संघीय सूची
- Provincial List - प्रांतीय सूची
- Concurrent List - समवर्ती सूची

Union
State

Residuary Powers → अवशिष्ट शक्तियाँ

- Given to:
- दी गई:
- Governor-General
- गवर्नर-जनरल को

Important → महत्वपूर्ण

- Proposed federation never came into operation because princely states did not join.
- प्रस्तावित संघीय व्यवस्था कभी लागू नहीं हो सकी क्योंकि देशी रियासतें इसमें शामिल नहीं हुईं।

GOVERNMENT OF INDIA ACT, 1935 — PROVINCIAL AUTONOMY



Question Practice

Dyarchy in Provinces - प्रांतों में द्वैध शासन

- Abolished
- समाप्त कर दिया गया। ✓

Provincial Autonomy - प्रांतीय स्वायत्तता

- Introduced responsible government in provinces.
- प्रांतों में उत्तरदायी शासन की शुरुआत की गई।
- Provinces allowed greater autonomy.
- प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई। ✓
- Governor required to act with advice of ministers in specified areas.
- निर्दिष्ट क्षेत्रों में गवर्नर को मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करना आवश्यक था।

Implementation - कार्यान्वयन

- Came into effect in 1937.
- 1937 में लागू हुआ। ✓

Dyarchy at Centre - केंद्र में द्वैध शासन

- Proposed introduction at Centre.
- केंद्र में द्वैध शासन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया। ✓
- Did not come into operation.
- यह लागू नहीं हो सका।